भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. †*105
मंगलवार, 11 फ़रवरी, 2025/22 माघ, 1946 (शक)को उत्तरार्थ

कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

†***105**. **श्री बस्तीपति नागराजूः**
श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) एआरडीबी के कम्प्यूटरीकरण के लिए बैंकवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई;
(ग) क्या राज्य सरकारें परियोजना में अपने हिस्से की धनराशि का निवेश करने में सक्षम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से एआरडीबी अब अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर पाएंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और कम्प्यूटरीकरण का यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा;
(च) आज तक राज्यवार एआरडीबी के कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है;
(छ) क्या सरकार के पास 'एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर' से आज तक जुड़े पीएसीएस की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं; और
(ज) यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ज): सदन के पटल पर एक विवरणी रखी गई है ।

श्री बस्तीपति नागराजू और श्री बी. के. पार्थसारथी द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में पूछे गए और दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 105 के संबंध में भाग (क) से (ज) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

(क) कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण के लिए प्राप्त और स्वीकृत कुल प्रस्तावों का राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक- I** पर संलग्न है । आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में कोई कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नहीं हैं ।

(ख) और (ग) परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार, राज्य सरकारों और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का हिस्सा क्रमश: 45%, 30% और 25% है । तदनुसार, परियोजना में राज्यों द्वारा अपना अंशदान किया जा रहा है । कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना के अधीन आबंटित निधि, जारी निधि और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर संलग्न है ।

(घ) और (ङ) ERP (एंटरप्राइज रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के प्रदर्शन में दक्षता लाता है । इसके अलावा, यह कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार लाता है, लेखांकन प्रथाओं और उधार, वसूली एवं संसाधन जुटाने की प्रणाली के मूल पक्षों में एकरूपता लाता है और उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार लाता है । कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभाग करने वाले राज्यों में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी की जानी है । इस परियोजना में हार्डवेयर का प्रापण, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट (FHR), फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट (FVR), लीगेसी डाटा का डिजिटलीकरण, ERP ऑनबोर्डिंग, गो-लाइव और डे-एंड शामिल है ।

(च) नाबार्ड द्वारा डिजिटलीकरण के विभिन्न चरणों पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDBs)/प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs)/राज्य सरकार/सिस्टम इंटिग्रेटरों के लिए प्रशिक्षण कराए गए हैं जिसका ब्योरा सारणीबद्ध रूप में **अनुलग्नक-III** पर संलग्न है ।

(छ) और (ज) दिनांक 28.01.2025 तक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड हुए पैक्स के आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सहित कुल राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक- IV** पर संलग्न है ।

****

अनुलग्नक-I

ARDBs कंप्यूटरीकरण के लिए प्राप्त और स्वीकृत कुल प्रस्तावों का राज्य-वार ब्योरा

क्रम सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव (ARDB इकाई की संख्या)	स्वीकृत इकाइयों (ARDBs) की कुल संख्या	स्वीकृत हार्डवेयर की कुल संख्या
1.	पुड्डुचेरी	2	2	17
2.	पंजाब	113	113	272
3.	जम्मू और कश्मीर *	51	51	115
4.	त्रिपुरा	6	6	15
5.	उत्तर प्रदेश	342	342	740
6.	कर्नाटक	207	207	467
7.	तमिलनाडु	216	216	477
8.	हरियाणा	90	90	203
9.	हिमाचल प्रदेश	88	88	202
10.	गुजरात	195	195	440
11.	राजस्थान	163	163	351
	कुल	**1473**	**1473**	**3299**

* जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र इस परियोजना से हट गया है क्योंकि इस क्षेत्र के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को नाबार्ड और एक विशेष ऑडिट की रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं माना गया है ।
नोट: पश्चिम बंगाल और केरल राज्य से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अनुलग्नक-II

ARDBs कंप्यूटरीकरण परियोजना के अधीन आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्योरा

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	भारत सरकार का आबंटन	भारत सरकार द्वारा जारी	राज्य का आनुपातिक हिस्सा	ARDB का आनुपातिक हिस्सा	कुल	कुल निधि का उपयोग
1.	गुजरात	4.96	0.82	0.55	0.46	1.82	0.00
2.	हरियाणा	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	हिमाचल प्रदेश *	3.39	0.56	0.06	0.21	0.83	1.86
4.	जम्मू और कश्मीर**	1.73	0.26	0.07	0.11	0.44	0.00
5.	कर्नाटक	5.27	0.80	0.53	0.44	1.78	1.78
6.	पुड्डुचेरी	0.18	0.04	0.01	0.02	0.07	0.05
7.	पंजाब	2.99	0.47	0.31	0.26	1.04	0.00
8.	राजस्थान	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	तमिलनाडु	4.96	0.82	0.55	0.46	1.82	1.37
10	त्रिपुरा	0.24	0.04	0.01	0.02	0.06	0.04
11	उत्तर प्रदेश	8.48	1.27	0.85	0.71	2.82	0.00
12	केरल	6.37	-	-	-	-	-
13	पश्चिम बंगाल	3.54	-	-	-	-	-
	कुल	**48.43**	**5.08**	**2.93**	**2.67**	**10.68**	**5.10**

* राज्य द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार ARDB ने 1.25 करोड़ रुपये का अपना कुल अंशदान जमा कर दिया है, अत: राज्य का कुल व्यय 1.86 करोड़ रुपये है ।

** जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र इस परियोजना से हट गया है क्योंकि इस क्षेत्र के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को नाबार्ड और एक विशेष ऑडिट की रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं माना गया है ।

अनुलग्नक-III

NABARD द्वारा प्रशिक्षित ARDBs के कर्मियों की राज्य-वार संख्या

क. राज्यों की ऑनबोर्डिंग और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट (FHR) में ARDBs के गठन और व्यवसाय का संकलन

उपस्थित राज्य	प्रतिभागियों की कुल संख्या
गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुड्डुचेरी, उत्तर प्रदेश	40
तमिलनाडु	680
ARDB परियोजना के अधीन सभी राज्य	2360

ख: फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट (FVR) के माध्यम से FHR डाटा का फील्ड सत्यापन

उपस्थित राज्य	प्रतिभागियों की कुल संख्या
पुड्डुचेरी, त्रिपुरा और गुजरात	55
कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और पंजाब	400
हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश	500

ग. डाटा कैप्चर टूल (DCT) पर ARDB/s का संकलित लीगेसी डाटा

उपस्थित राज्य	प्रतिभागियों की कुल संख्या
गुजरात	80
उत्तर प्रदेश	100
हिमाचल प्रदेश	40
पंजाब	40

अनुलग्नक-IV

एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सॉफ्टवेयर के साथ ऑनबोर्ड किए गए कुल पैक्स का राज्य-वार ब्योरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कंप्यूटरीकरण के लिए चयनित पैक्स	ERP पर ऑनबोर्ड
1.	महाराष्ट्र	12,000	10,979
2.	राजस्थान	6,781	4,206
3.	गुजरात	5,754	5,249
4.	उत्तर प्रदेश	5,686	2,978
5.	कर्नाटक	5,491	2,077
6.	मध्य प्रदेश	4,536	4,516
7.	तमिलनाडु	4,532	4,529
8.	बिहार	4,495	4,440
9.	पश्चिम बंगाल	4,167	1,103
10.	पंजाब	3,482	1,720
11.	आंध्र प्रदेश	2,037	1,734
12.	छत्तीसगढ़	2,028	2,010
13.	हिमाचल प्रदेश	1,789	836
14.	झारखंड	1,500	1,467
15.	हरियाणा	710	617
16.	उत्तराखंड	670	185
17.	असम	583	580
18.	जम्मू और कश्मीर	537	531
19.	त्रिपुरा	268	245
20.	मणिपुर	232	45
21.	नागालैंड	231	33
22.	मेघालय	112	103
23.	सिक्किम	107	107
24.	गोवा	58	35
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46	46
26.	पुड्डुचेरी	45	37
27.	मिजोरम	25	25
28.	अरुणाचल प्रदेश	14	11
29.	लद्दाख	10	9
30.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	2
	कुल	**67,930**	**50,455**